SHRISHANKAR ROY CHOWDHURY: Sir, I would like to know whether the Indian and the Bangladesh Governments have now worked out an accepted procedure by which the Bangladesh Government will accept illegal migrants being pushed back or deponed to Bangladesh under the recent Foreign Secretary level talks ?

SHRI VTNOD KHANNA: Sir, unfortunately, even up to this date, Bangladesh has not accepted that there is illegal migration in India. They don't even accept the fact that there is illegal migration in India. But, whenever we have investigated, verified these people, and taken them to the border, they have accepted these people; they have been cooperative with us. But there is no such established procedure by which they will take back the nationals whom we identify. After all we are the complainants. We have to prove that they are non-nationals; we have to prove that they are Bangladeshi nationals. Then, they will verify and take the people back.

श्री सभापति : मैं माननीय विदेश मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह समस्या सारे राज्यों में हैं । इस समस्या के संबंध में आप राज्यों की सरकारों के साथ बैठकर, बात करें और कोई ऐसा प्रोसीजर निकालें जिस से आप को समय-समय पर जानकारी मिलती रहे ओर आप उन की रोकथाम कर सकें ।

Mobile telephone facility

*662. SHRI KALRAJ M1SHRA: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether certain regions in the country are still deprived of the mobile telephone facility;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to provide these areas with such facilities?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF DISINVESTMENT (SHRI ARUN SHOURIE): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) Consequent to the grant of licenses for Cellular Mobile Telephone Sen ice (CMTS) to private operators. Cellular Services were first started in the four Metro City Service Areas of Delhi, Mumbai. Kolkata and Chennai from August, 1995 onwards and thereafter in the Telecom Circle Service Areas beginning December. 1996. After adoption of New Telecom Policy-1999

(NTP-99) and shifting of the existing operators to the revenue sharing regime of NTP-99, additional licenses were granted to private operators: The cellular sen ice has been progressively rolled out by the private operators in the district headquarters and towns. According to information furnished by the Cellular Operators Association of India, about 1640 district headquarters and towns in various service areas across the country had been covered with the cellular service by March. 2003. Mahanagar Telephone Nigam Ltd. started its cellular sen ices from February, 2001 in Delhi and Mumbai. Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) also started providing the services in most parts of the country from October. 2002 and have so far covered about 1020 cities and towns with the cellular sen ice by March, 2003. Private operators coupled with the Government operators are expected to cover more and more places with the Cellular Senice over a period of lime.

The terms and conditions of the Licence for CMTS require that in the Metro City Sen ice Areas an operator has to cover 90% of the Sendee Area within one \ car. and in the Telecom Circle Senice Areas, 10% of the District Headquarters within ons year and 50% of the District Headquarters within three years. The licensee is also permitted to cover any other town in a district iniieu of the District Headquarter. The choice of District Headquarters/towns to be covered and further expansion beyond 50% District Headquarters/towns shall lie with ihe licensee depending on his business decision. There is no mandatory requirement for coverage of 100% of the districts as well as coverage of rural areas.

Expansion for fresh start of CMTS in J&K. Assam and North East Telecom Circles was not permitted earlier on considerations of security. Tins was however permitted with effect from 21st August, 2002. Accordingly? BSNL has plans to launch its cellular senices in Jammu and Kashmir in the near future. BSNL also has plans to launch its cellular senices in Assam and North East Telecom Circles during the current financial year.

श्री कलराज मिश्र : सभापति जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है कि निजी प्रचालकों के द्वारा, जो निजी मोबाइल सेल्युलर कंपनी हैं उनके द्वारा जिला मुख्यालयों और मुख्य-मुख्य शहरों मे ही ज्यादातर यह सुविधा प्रदान की गई हैं, भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र इससे वंचित हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने प्रतिशत क्षेत्र हैं, जो इस सुविधा से वंचित हैं और इसके साथ ही साथ इस दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो ऐसे सुविधारहित क्षेत्र हैं उनमें कितने स्थानों पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी ?

श्री अरूण शौरी : सभापति जी, एक्चुअली यह सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन की ग्रोथ इंडिया में बहुत फास्ट हुई हैं, आज लगभग 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर इसके हैं । इसमें सबसे ज्यादा तेजी से पिछले 7-8महीने में जो सर्विस एक्सटेंड कर रहे हैं, वह एक्चुअली प्राइवेट कंपनी नहीं हैं बल्कि बीएसएनएल हैं । इसने पिछले 7-8 महीने में 22.5 लाख सब्सक्राइबर कैप्चर किए हैं । मिश्रा जी की यह बात ठीक हैं कि पहले ऐसी समस्या मेट्रोपोलिटन शहरों में आएंगी । आपको सुनकर खुशी होगी कि आज 1640 डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और छोटे टाऊन, कस्बों में यह सर्विस फैल चुकी हैं । जैसे-जैसे यह टॉवर एक्सटेंड होते जाएंगे तो नेचुरली विलेज एरिया भी कवर होगें । दसवीं योजना में तो इसका एक्स्टैंशन होने की बहुत ही जरूरत हैं और जैसा मैंने पिछली बार आपसे अर्ज किया था, बीएसएनएल को इसमें तकरीबन 29 हजार करोड़ रूपया चाहिए और अगर हम उसको फैसिलिटी नहीं देंगे या रिसोर्स कमाने नहीं देंगेतो दिक्कत होगी । इसमें कोई शंका नहीं कि इस प्लान में इन्हें केवल 4 करोड़ रूपए ही दिए गए हैं अगले चार साल के लिए ।

श्री कलराज मिश्र : मान्यवर, निजी मोबाइल सेल्युलर कंपनी हैं उनकी सेवाएं हैं उसकी दर में लगातर कमी हो रही हैं वे अपने रेट घटाते चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार स्तर पर बेसिक फोन सेवा की जो दरें हैं, वे बढ़ाने के हिसाब से बनाई जा रही हैं । यह एक अति गंभीर विषय दिखाई पड़ता हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में विचार करते हुए उस सेवा की दरों को घटाने की दिशा में प्रयत्न करेंगे, जिसके कारण किसी प्रकार की आशंका आम आदमी के मन में न निर्माण हों ?

श्री अरूण शौरी : सर,एक्चुअली हरेक तरह से टेलीफोन रेट बहुत कम हो रहे हैं, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : सुनिए,सुनिए । आप सुनिए । ...(**व्यवधान**)...

SHRI ARUN SHOURIE : Sir, I will come to *ihat....(Intemtptions)*

SHRI A. VIJAY ARAGHAVAN: Sir, the Minister is not paying from his own pocket *(Interruptions)*

श्री सभापति : यह मैं एलाऊ नहीं करूंगा । आप सुनिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं ? ...(**व्यवधान**)...

SHRI ARUN SHOURIE : Sir, there is one element which is of great concern to tlie Members and to the general public; I entirely agree. But in the new order ofTRAI. charges for calls from fixed lines to cellular lines, उनमें क्योंकि पल्स रेट 60 सेकेंड कर दिए गए हैं और उसके चार्ज जरूर ज्यादा हो गए हैं ।. *(Interruptions)*

श्री सभापति : आप सुनिए तो सहीं ।...(**व्यवधान**)...

SHRI ARUN SHOURIE : Sir, all the other rates are coming down, आप इजाजत दें तो मैं बता दूं।

श्री सभापति : जी, बता दीजिए। ....(**व्यवधान**)...

श्री अरूण शौरी: सर, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो आपकी बहुत स्ट्रोंग फीलिंग हैं, वह मैं ट्राइ के चेयरमैंन को और मैम्बर को आज ही बतलाऊंगा। कल भी मैंने उनसे बात की हैं, आज भी बतलाऊंगा, मगर इसमें कोई सात-आठ महीने की कंसलटेशन के बाद उन्होंने यह सब रेट तय किए हैं। एक रेट को तय किया जाएगा तो फिर यह होगा कि रूरल एरिया के लिए जो रिसोर्स चाहिए वह नहीं हो पांएगी, मगर आपकी आशंका मैं जरूर सबको पहुंचाऊंगा।...(**व्यवधान**)...मगर जो न चेंज हो आप मुझे बताएंगे कि क्या-क्या नहीं चेंज चाहिए क्योंकि इसमें बहुत भ्रम हैं। बीएसएनएल के रेट में जो मंथली रेंट हैं, न तो रूरल सब्सक्राइबर के लिए और ही अर्बन सब्सक्राइबर के लिए चेंज किया गया हैं। लोकल काल्स के लिए पल्स रेट जो 180 सैकिंड्स का था, जिसको " टीआरएआई" ने कहा था कि कम करो, वह कम नहीं किया गया। आईएसडी काल्स के लिए काल रेट्स चेंज नहीं किया गया। रूरल सब्सक्राइबर की जो डेफिनेशन "टीआएएआई" ने चेंज की थी, जैसा मैने आपसे पहले अर्ज किया था, हमने उनको रिप्रजेंट किया – क्योंकि अगर हम उस डेफिनेशन को चेंज करते तो रूरल सब्सक्राइबर जो करीब एक करोड़ हैं, उसमें से 80 लाख सब्सक्राइबर नान रूरल हो जाते- उन्होंने अपना वह आर्डर रिसिंड करके पुरानी डेफिनेशन रहने दीं।

सर, एसटीडी काल्स में बहुत कमी हुई हैं। आप देखिए कि एसटीडी काल जो विद इन दि सर्कल हैं, उसमें "टीआरएआई" ने 8.40 रूपए प्रति मिनट अलाऊ किया था मगर "बीएसएनएल" ने उसको 2.40 रूपए प्रति मिनट रखा है, " टीआरएआई" ने भी कुछ सोचकर, कॉस्ट वगैरह का सोचकर और कितने रिसोर्सिज चाहिए, यह सोचकर वह किया था, यानी जैसे मध्य प्रदेश में आप कहीं से कहीं काल कर लीजिए, इतने बड़े प्रान्त में रेट अनचेंज रहेंगे। दूसरे जो इंटर सर्कल एसटीडी रेट्स हैं, वे वहीं रहेंगें, वे चेंज नहीं किए गए। फिक्स टू इंटर सर्कल एसटीडी काल्स 200 किलोमीटर से ज्यादा, जो पहले 4.80 रूपए थी, उसे कम करके 3.60 रूपए प्रति मिनट रखा गया हैं जबकि "टीआरएआई " ने कहा था कि इनको इन्क्रीज़ कर दीजिए 8.40 रूपए प्रति मिनट। तो, सर,इसी तरह से बाकी चीजें हैं। यह एक प्वाइंट जरूर ठीकहैं,कई माननीय सदस्यों ने मुझे अभी कहा है और कल भी यह कहा गया है कि जो फिक्स लाइन से सेलुलर रेट्स हैं, वे क्योंकि ज्यादा कर दिए गए हैं, इसका लोगों पर बहुत असर पड़ा हैं और उसमें यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि गनर्वमेंट की कम्पनीज रेट इन्क्रीज़ कर रही हैं, इससे सेलुलर कम्पनीज को फायदा होगा। मैं इस बारे में उनसे जरूर बात करूंगा। सर, फाइनल अथॉरिटी उनकी

हैं । अंडर दि एक्ट, जो एक्ट आपने पास किया है, उसके अनुसार फाइनल अथॉरिटी उनकी हैं, मगर मैं उनसे बात करूंगा । *(Interruptions)* It is a policy decision. I will put it to the Prime Minister, *(Interruptions)*

श्री नीलोत्पल बसु : आप अमेंडमेंट क्यों नहीं लाते ? **...(व्यवधान)....**

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : The hon. Minister should assure the House in this regard. *(Interruptions)*

श्री सभापति : श्री संजय निरूपम । **...(व्यवधान)...**

SHRI NILOTPAL B ASU : This is *the* precise question we are raising. You have to define public interest', and amend the law. *(Interruptions)*

श्री सभापति: उन्हें बोलने दीजिए । श्री संजय निरूपम ।

श्री प्रेम गुप्ता : सर, जब "टीआरएआई" को पास किया था तब सरकार ने यह कहा था कि हम पूरा कंट्रोल रखेंगे और अब बोलते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं हैं ।

श्री संजय निरूपम : सभापति जी, पिछले महीने भी जब इस विषय पर हमने आधे घंटे की चर्चा की थी तब भी मंत्री जी ने यही का कहा था कि मैं "टीआरएआई" से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि सब लोगों को रिलीफ मिले । पता नही इंन्होंने क्या बातचीत की । अंतत: जो बेसिक टेलीफोन यूजर हैं, जो इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला वर्ग है,उसके ऊपर इससे असर पड़ा है । मंत्री जी ने कहा कि सिर्फ पल्स रेट कम किया गया है । तीन मिनट का यदि एक मिनट करेंगे तो वैसे ही टैरिफ बढ़ जाएगा । तो पहला तो मेरा निवेदन यह हैं कि अगर "टीआरएआई" का बिल हमने पास किया और उस कानून के तहत आप उनके मामले में इंटरफियर नहीं कर सकते तो "टीआरएआई" के बारे में एक अमेंडमेंट लाया जा सकता हैं ।

सभापति जी दूसरे "टीआरएआई" में एक प्रोविजन हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार कभी भी "टीआरएआई" के किसी भी डिसीजन को रोक सकती हैं । तो पब्लिक इंटरेस्ट यह है कि बेसिक टेलिफाने मंहगा हो चुका हैं । अब बेसिक टेलिफोन महंगा हो चुका है तो उसको सस्ता करने के लिए, हम सबकी मांग के अनुसार , जितनी जल्दी हो सके क्या माननीय मंत्री जी इस पूरे नए टैरिफ को रोल बैंग करेंगे ?

श्री सभापति : मंत्री जी, एक बात मैं भी जानना चाहता हूं क्योंकि मैं उस समय यहां नहीं था जिस समय यह "टीआरएआई" का कानून पास हुआ था कि क्या इस कानून में यह व्यवस्था है कि सैंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहे तो वह "टीआरएआई" को निर्देश दे सकती हैं ?

श्री नीलोत्पल बसु: हां, दे सकती हैं...**(व्यवधान)....**

श्री सभापति : एक मिनट ठहर जाइए । **...(व्यवधान)...**सबको बोलने की जरूरत नहीं हैं ।

श्री संजय निरूपम : सर, एक प्राविजन हैं । मंत्री जी को सब मालूम हैं। "टीआरएआई" की एक धारा यह कहती है कि अगर "टीआरएआई" का कोई निर्णय जनहित के खिलाफ है तो सरकार उस निर्णय के मामले में इंटरफियर करके "टीआरएआई" के निर्णय को रोक सकती हैं । यह व्यवस्था हैं ।

श्री अरूण शौरी: सर, "टीआरएआई" का जो एक्ट हैं, उसमें **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : मंत्री जी, आप बोलिए ।

श्री अरूण शौरी : मेरे लिए बहुत आसान हैं यह कह देना कि रोल बैक कर दूंगा या यह कर दूंगा, मगर ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा । वह सैक्शन मैंने पिछली बार भी पढ़ा था, जब नीलोत्पल जी ने यह क्वेश्चन उठाया था । उसमें आप देखिए कि किस चीज के कारण आपने अथॉरिटी दी हैं । Power of the Central Government to issue directions आपने यही सवाल पूछा हैं ?The Central Government may, from time to time, issue to the authority such directions as it may think necessar^ in the interest of:

sovereignty and integrity of India;
security of the State;
friendly relations with foreign States;
public order, decency or morality. *(Interruptions)*

श्री सभापति : आप बैठ जाइए । **...(व्यवधान)...** आप यह कर क्या रह रहे हैं ? संजय निरूपम, कृपया आप यह बता दीजिए कि डायरेक्शन यहीं हैं न जो आपने सुने हैं ?

श्री संजय निरूपम : मेरे ख्याल से आर्टिकल 53 हैं ।

श्री अरूण शौरी: सैक्शन 25 हैं ।

SHRI SANJAY NIRUPAM: Yes.

श्री सभापति :अब यह कानून आपने पास किया, डायरेक्शन क्या दिए जा सकते हैं, इस संबंध में आपने व्यवस्था की हैं । अब इस संबंध में जो डायरेक्शन दिए गए हैं, जो आपके रेट्स बढ़े हैं वे इस संबंध में तो हैं नहीं, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, यह बता दीजिए ।

श्री संजय निरूपम : सभापति जी**...(व्यवधान)...**

SHRI JANARDHANA POOJARY : The Government can give direction. ... *(Interrruptions)...* The Government can give direction if it feels that there is something against the country.... (Interruptions)...

श्री सभापति : ठहरिए आप**…(व्यवधान)….**

SHRI JANARDHANA POOJARY : You repeal the Act.. *(Interruptions)...*

श्री सभापति : नहीं, रिपील नही, कर सकते, वह कानून आपने पास किया है **…(व्यावधान)**...

I will not allow ...*(Interruptions)*.... Nothing will go on record, **बिल्कुल नहीं**... *(Interruptions),..*

SHRI JANARDHANA POOJARY :*

SHRI N. K. PREMACHANDRAN :*

SHRI NILOTPAL BASU :*

SHRI MANOJ BHATTACHARYA:*

SHRI JANARDHANA POOJARY : The country is supreme. ..*(Interruptions)...* The Parliament is supreme .....*(Interruptions)* ... They can . come forward with an amendment .....*(Interruptions)....*

श्री सभापति : मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम हैं**….(व्यवधान)…**आप बैठिए। क्वेश्चन यह नहीं हैं**…(व्यवधान)** यह कानून किसने पास किया हैं ? आप यह कहिए कि गर्वनमेंट इसमें अमेंडमेंट करे तो बात समझ में आती हैं। अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं हैं **….(व्यवधान)**

श्री संजय निरूपम : सभापति जी, मेरा निवेदन यह हैं कि टेलीकॉम सैक्टर में रोज विस्तार हो रहा हैं, विकास हो रहा हैं। आपने पूछा कि TRAI किसने पास किया ? बिल्कुल हमने पास किया हैं लेकिन**…(व्यवधान)…**

श्री सभापति : आप बैठिए तो सही**….(व्यवधान)…**

श्री संजय निरूपम : अगर किसी क्लाज से जनता के हित के खिलाफ कुछ काम हो रहा हैं तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसमें अमेंडमेंट लाए और जनता के हित के बारे में पहले सोचे**….(व्यवधान)…**

श्री सभापति :मैं एलाऊ नहीं करूंगा, Nothing will go on record.... *(Interruptions)...* आपका क्वेश्चन यह था कि क्या गवर्नमेंट TRAI के प्रपोजल के मामले में उनको खत्म करने या चेंज करने की डायरेक्शन दे सकती हैं ? नहीं , as per Act वह डायरेक्शन नहीं दे सकती**…**

*Not recorded.

(**व्यवधान**)...पब्लिक आर्डर नहीं आएगा । आप ज्यादा से ज्यादा मंत्री महोदय को हाऊस की तरफ से यह कहिए कि इसके ऊपर से विचार करे, TRAI से बात करे और यदि कानूनी अधिकार देना है तो माननीय सदस्य उस एक्ट में अमेंडमेंट मूव कर दें, उस पर विचार हो जाएगा । अब यह मामला आगे नहीं चलेगा । Next Question.

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, आपने हमको आश्वस्त किया था कि आप हमको सवाल पूछने देंगे लेकिन फिर आप आगे बढ़ गए ।

श्री सभापति: आप भले आदमी हो, आप क्या टेलीफोन की बात करते हों ।

श्री लालू प्रसाद : नहीं, हम तो दूसरी बात कहना चाहते हैं ।

श्री सभापति : आप विश्वास करिए, जो मैंने कहा हैं...(**व्यवधान**)...

डा.अबरार अहमद: महोदय, इधर से किसी को मौका नहीं दिया गया ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति : मौका सबको दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं हैं । यह गलत बात मत कहिए ...(**व्यवधान**)आप बैठिए ।

श्री लालू प्रसाद: सभापति महोदय, यह फोन एक भारी झंझट का घर है । इससे अपराधियों का चारों तरफ संपर्क कायम होता हैं । आप इसको बंद करिए, समाप्त करिए । पहले जो P&T का था, उसी को रखिए । इसके द्वारा सारे अपराधी मलेशिया से, थाईलैंड से मॉनीटरिंग कर रहें हैं...(**व्यवधान**)...घर से फोन आता हैं कि कहां पर हों ? पति को बोलना पड़ता हैं कि हम चांदनी चौक पर पहुंच गए हैं । हटाइए इसको ।

श्री सभापति: जिन पत्नियों को पतियों पर विश्वास नहीं होता, वे ऐसा काम करती हैं । अगर आप में विश्वास नहीं हैं तो यह हाऊस की जिम्मेदारी नहीं हैं ....(**व्यवधान**)

BSNL's commercial operation in A.P.

*663. SHRIS. M. LALJAN BASH A: WiU the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that BSNL has not rationalised its commercial operation in Andhra Pradesh;

(b) what is the new system for payment of bills which are delayed by a few days;

(c) whether it is a fact that customers have to travel 70 miles or more to pay bills which are delayed;